Media Outreach

4th Anniversary Celebration of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SMPRM)
Table of Contents

1. अनुभाग अ: मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति
   i. हिंदी भाषा में प्रेस विज्ञप्ति
   ii. प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी विज्ञप्ति

2. Section A: Press Release by Ministry
   i. English Press Release
   ii. Press Release by Press Information Bureau (PIB)
   iii. Pictures on the program of 4th Anniversary (24.02.2020) of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission

3. अनुभाग ब: SPMRM की चौथी वर्षगांठ पर प्रेस कवरेज
   i. अमर उजाला: शहरों की तरह गाँवों की सूरत संवारेगा : रब्बन मिशन
   ii. रुब्बन मिशन में भारतीय संस्कृति और परंपरा की भावना का समावेश है : तोमर
   iii. Newspaper coverage from State of Jharkhand
   iv. Newspaper coverage from State of Chhattisgarh

4. Section B: Press Coverage on occasion of 4th Anniversary of SPMRM
   i. DD News-Shyama Prasad Mukherji National Rurban Mission completes four years
   ii. All India Radio-Shyama Prasad Mukherji National Rurban Mission completes four years
   iii. Business Standard-Rurban Mission embodies spirit of Indian culture of community living: Narendra Singh Tomar
   iv. Dariya News-Narendra Singh Tomar inaugurates the 4th anniversary celebration of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission
   v. THE WEEK- Rurban Mission embodies spirit of Indian culture of community living: Narendra Singh Tomar
   vi. Outlook- Govt to encourage formation of “Cluster villages”
   vii. INDUS DICTUM-NITI Aayog proposes to extend Rurban Mission(SPMRM) to over 1000 clusters
viii. India Education Diary- 4th Anniversary of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) on 21st February, 2020

ix. National Web News-Union Rural Development Minister Narendra Singh Tomar initiates The 4th Anniversary Celebration of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission

x. All India Radio-Govt plans to construct 1,000 more urbanized clusters in rural areas, says Rural Development Minister Narendra Singh Tomar

xi. Newspaper coverage from the State (Mizoram, Telangana)

xii. The Indian Awaaz- Govt to construct 1,000 more urbanized clusters in rural areas

xiii. Newspaper coverage from the State (Gujarat, Andhra Pradesh)

5. Section C: Social Media

i. SPMRM- Tweets
अनुभाग अः
मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के शुभारंभ की चौथी वर्षगांठ पर

राष्ट्रीय अनुभव, आदान प्रदान कार्यक्रम

24 फरवरी 2020, डॉ.अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली

ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) की चौथी वर्षगांठ समारोह के अवसर पर एक राष्ट्रीय स्तर का अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम डॉ.अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में 24 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की।

इस आयोजन में 600 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और प्रेस के सदस्यों के के साथ-साथ क्लस्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन देश भर में क्लस्टर द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा तथा क्रिटिकल गैप फंडिंग के तहत प्रदान किए गए संसाधन उपयोग की जागरूकता और पैरवी करने के दोहरे उद्देश्य के साथ किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में संयुक्त सचिव, डॉ. बिस्वजीत बैनर्जी ने माननीय प्रधानमंत्री के संदेश “आत्मा गाँव की सुविधाओं शहर की” संदेश का उल्लेख करते हुए प्रतिभागियों का स्वागत किया। तमिलनाडु में सुतामलिक क्लस्टर, मिजोरम में ऐबक क्लस्टर और उत्तर प्रदेश के पटेहरा कला क्लस्टर में निर्मित की जा रही जा रही विभिन्न आर्थिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के प्रदर्शन के लिए एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान, माननीय मंत्री ने 18 बिहिन्र राज्यों से संकलित 50 सफलता की कहानियों पुस्तक का विमोचन किया, जो इन जैविक विकास केंद्रों की आकांक्षाओं का ज्ञात देती है।

माननीय मंत्री जी ने जियो रुबन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जो मिशन के तहत किए गए कार्यों को तुरंत पंजीकृत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और क्लस्टर में किये गए कार्यों की प्रगति के भू-संदर्भित हस्ताक्षर के साथ लोगों के इंटरफेस की सुरुआत है।

अपने सम्बोधन के दौरान, माननीय मंत्री ने कहा कि रुबन (एसपीएमआरएस) एक 'भारतीय प्रयोग' है जिसमें सहकारी संघ और राज्यों के अधिकारियों के साथ-साथ जनता की आंदोलन की सहायता के लिए एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता की सहायता के लिए इस व्यापक विकास के दृष्टिकोण के लिए एसपीएमआरएस द्वारा उठाए गए कदमों की स्तर में जगह रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि हमें ग्रामीण भारत की वर्तमान चुनौतियों को अलग नजरिये के साथ अभिसरण तथा उन्नति के अवसरों के अनुकूल देखने की आवश्यकता है।

माननीय राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने सम्बोधन में कहा कि, रुबन मिशन के माध्यम से लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं और इसलिए कई विकास विकल्प संभव हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्लस्टर के विकास से हमारे शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण ने बताया कि, मिशन के प्रारंभ होने के बाद से, 288 क्लस्टर की एकीकृत क्लस्टर विकास योजना विकसित की गई है और संबंधित राज्यों द्वारा 240 क्लस्टर की विस्तृत परियोजना
प्रत्येक को मंजूरी दी गई है, जहां पहले से ही जमीनी स्तर पर विकास कार्य प्रारंभ हो गए हैं। इन क्लास्टर्स में ₹ 28,075 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से ₹ 6,689 करोड़ रुपये के कार्य पहले ही किया गया है। उन्होंने मिशन के माध्यम से हो रही विभिन्न योजनाओं के अभियंताओं पर भी जोर दिया।

13 राज्यों के पंचायतों के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और अधिकारियों ने अपने क्लास्टर विकास के अनुभवों का आदान प्रदान किया। जिला परिषद प्रकाशम जिले के सीईओ, श्री कैलाश गिरीश्वर ने रोजगार के विभिन्न विकल्पों की व्याख्या की और बताया कि रिव्हर्स माइग्रेशन हो रहा है। श्री मयूर दीक्षित, सीडीओ, उद्यम सिंह नगर उत्तराखंड के साथ पंचायतों के प्रतिनिधियों ने पहेनिया क्लास्टर में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास पर केंद्रित निवेश संगठनी के आयोजन के बारे में बताया। उनके द्वारा निजी क्षेत्र के निवेश और कॉर्�पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) का समर्थन प्राप्त करने के प्रयासों के बारे में भी बताया गया। इसी प्रकार, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, मिजोरम और पंजाब के प्रतिनिधियों ने बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ क्लास्टर्स में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की प्रगति पर प्रदर्शन दिया।

इस आयोजन में श्री प्रशांत कुमार, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, तथा अन्य मंत्रालयों से जैसे पंचायती राज मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन (एसपीएमआरएम) की चौथी वर्षगांठ 21 फरवरी, 2020 को मनाई जाएगी।

बढ़ते शहरीकरण वाले 300 ग्रामीण क्लास्टर की समयभारत्म एवं समग्र ढंग से विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

ग्रामीण क्लास्टर की सफलता से उत्साहित होकर नीति आयोग ने अगले तीन वर्षों में 1000 से भी अधिक क्लास्टरों के लिए एक नये एवं विस्तारित कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है।

Posted On: 20 FEB 2020 6:44PM by PIB Delhi

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन (एसपीएमआरएम) के शुभारंभ की चौथी वर्षगांठ कल यानी 21 फरवरी, 2020 को मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकास की दहलीज पर पहुंच चुके ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने वाले कदमों को उठाने के विज्ञ के साथ 21 फरवरी, 2016 को इस मिशन को तौंचा किया था।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किये गये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन के तहत ग्रामीण संबंधी नियोजन के जरिए क्लास्टर आधारित एकीकृत विकास पर फोकस किया जाता है। देश भर के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्लास्टरों की पहचान की जाती है, जहां शहरी उनके में वृद्धि, गृह-कृषि रोजगारों के उच्च स्तर, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और अन्य सामाजिक-आर्थिक पैमाने जैसे शहरीकरण के बढ़ते संकेत मिल रहे हैं।

मिशन का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास का नई गति प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुधारस्थित ग्रामीण क्लास्टरों का सुधार करने के इस ग्रामीण क्लास्टर में व्यापक बदलाव लाना है।

इससे संबंधित क्षेत्र का समग्र विकास होगा और एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मिशन के तहत 300 ग्रामीण क्लास्टर की समयभारत्म एवं समग्र ढंग से विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इनमें से 296 क्लास्टर का चयन किया गया है और 288 एकीकृत क्लास्टर कार्य योजनाओं (आईसीएपी) को स्वीकृति दी गई है। 240 क्लास्टर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स की मंजूरी दी गई है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन दरअसल केंद्र प्रायोजित एक प्रमुख योजना है। इस मिशन में धनराशि या बितल से जुड़े दो घटक हैं: (1) विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों, सीएसआर कोष के जरिए रूपांतरित धनराशि और (2) कम पड़ ही अल्पतात्विक धनराशि का इंतजाम (सीजीएफ)। इनमें गैर-जनजातीय क्लास्टरों के लिए प्रति क्लास्टर 30 करोड़ रुपये तक और जनजातीय एवं पहाड़ी राज्यों वाले क्लास्टरों के लिए प्रति क्लास्टर 15 करोड़ रुपये तक के सीजीएफ का प्रावधान किया गया है।

मौजूदा समय में, अब तक जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी वाली कुल धनराशि 1,842.97 करोड़ रुपये है। 288 आईसीएपी में 28,075 करोड़ रुपये के कुल निवेश को मंजूरी दी गई है। विभिन्न योजनाओं से रूपांतरित धनराशि 21,194 करोड़ रुपये और 6882 करोड़ रुपये है। इनमें से कुल व्यय 30 नवम्बर, 2019 तक 6,689
करोड़ रुपये का हुआ, जिसमें से 5619 करोड़ रुपये रूपांतरित धनराशि के रूप में थे, जबकि 1071 करोड़ रुपये सीजीएफ के लिए थे। इसके तहत जारी की जा रही सीजीएफ धनराशि के 31 मार्च, 2020 तक बढ़कर 1,200 करोड़ रुपये का लक्ष्य पार कर लेने की आशा है।

इन समूहों में नियोजित इनक्राउंटर के हर महीने लगभग 24x7 पानी की आपूर्ति, परेलू और क्लास्टर स्तर पर ठोस और तरल आपूर्ति प्रबंधन की सुविधा, क्लास्टर के गांवों में और गांव के बीच की सड़कों का प्रवाह, हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा शामिल है। क्लास्टर में आर्थिक सुविधाओं में कृषि सेवाओं एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में विभिन्न विषयवस्तु क्षेत्र, परिवहन और लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोशिश विकास को शामिल किया गया है।

एसीएमआरएम क्लास्टर शासन स्तर पर आधार-रेखा सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित किए गए निम्नलिखित स्थलों से चयनित हस्तक्षेपों पर केंद्रित करते हैं:

(i) स्थलता, (ii) पाइप द्वारा जलपूर्ति, (iii) ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, (iv) ग्रामीण सड़क पर प्रभाव और विज्ञानकरण, (v) नालियों से सवार होने वाली गांवों की सड़कों पर पहुँच, (vi) अंतर ग्रामीण सड़क संपर्क, (vii) सार्वजनिक परिवहन, (viii) आर्थिक संविधानों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण, (ix) कृषि-सेवा प्रसंस्करण और संबंध गतिविधियों, (x) स्वास्थ्य, (xi) शिक्षा, (xii) डिजिटल साक्षरता, (xiii) नागरिक सेवा केंद्र, (xiv) एलपीजी गैस कनेक्शन, (xv) पर्यावरण, (xvi) रोजगार सुधार और स्वास्थ्य प्रशिक्षण। (xvii) घरेलू अवसर, (xviii) इंजीनियरिंग, (xix) सामाजिक अवसर, (xx) ग्रामीण आवास (xxi) समाज कल्याण।

इसके अलावा, ग्रामीण योजना भुन्तालय मिशन की जमीनी प्रगति में तेजी लाने के लिए कदम उठा रहा है। मिशन सभी चिन्हित कार्यों का कुल दौर के लिए दो साल का वित्तीय बजट है। मंत्रालय को कई प्रथम और कई राज्यों तथा निर्वाचित अधिकारियों के तरफ से और अधिक रूढ़िवाले क्लास्टर आवार्तित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। नीति आयोग ने इस मंत्रालय को कहा है कि रुढ़िवाले क्लास्टरों की सफलता से निरंतर सीख के आधार पर आगे चलने वाले 1000 से अधिक क्लास्टरों के लिए एक नए और विस्तारित कार्यक्रम की योजना बनाई जा सकती है।

इसका उद्देश्य समेकित और समय आधारित प्रणाली के तहत आर्थिक विकास केंद्रों के साथ सभी बृन्दावनी सुविधाओं से लेते अवसरों जाने के लिए एक नया और स्वास्थ्य शहर की.......’ के आधार पर किया जाना है।

*****

एस.शुक्ला/एएम/आरआरएस/एके/एकेपी/बाईबी/सीएस/डीए – 5865

(Release ID: 1603897) Visitor Counter : 173

Read this release in: English , Urdu
Section A:
Press Release by Ministry
Press Release

National Experience Sharing on fourth anniversary of launch of
Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission

24th February 2020, Dr. Ambedkar International Centre, New Delhi

Ministry of Rural Development organised a National level experience sharing on the occasion of fourth anniversary celebration of launch of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) at Dr. Ambedkar International centre, New Delhi. The event was chaired by Shri Narendra Singh Tomar, Hon’ble Minister of Rural Development, Panchayati Raj and Agriculture & Farmers Welfare.

The event saw participation from over 600 panchayat members, SHG members and officials representing Rurban clusters from across from 27 States, UTs as well as officials from Ministries and member of Press.

The event was organised with a dual purpose of appreciating progress made by clusters across the country as well as build to raise awareness and advocacy for the Mission to ensure optimisation of resource use provided under Critical Gap Funding mechanism.

At the outset, Joint Secretary Dr. Biswajit Banerjee extended welcome to the participants mentioning the message of Hon’ble Prime Minister, ‘आत्मा गाँव की सुविधाएं शहर की’. A short film on success stories related to Suttamalli cluster in Tamil Nadu, Aibawk cluster in Mizoram and Patehara Kala cluster from Uttar Pradesh was screened to showcase the different economic and social infrastructure being created in the clusters.

During the event, the Hon’ble Minister released a compendium of 50 success stories from across 18 States which gives a glimpse of aspirations of these organic growth centres.

The Hon’ble Minister also launched the GeoRurban mobile app which is a digital platform for instantly registering works carried out under Mission and is the beginning of people interface with geo-referenced signature of progress of works in their cluster.

During his address, the Hon’ble Minister stated that Rurban (SPMRM) is a ‘भारतीय प्रयोग’ with a focus on achieving rural aspiration through co-operative federalism. He stressed that the panchayat and SHG leaders must focus on and strive for viewing their cluster development comprehensively and ultimately
targeting convergence of all schemes. He appreciated the steps taken by SPMRM for this comprehensive development approach. Further, he mentioned that we need to view the current challenges of rural India with changed lens – from the perspective of convergence and optimisation of resource use coupled with employment generation opportunities. Thereby, we can create several new livelihood options within the clusters imparting economic sustainability. He concluded by stating that, building upon the learnings from the implementation of the Mission in the 288 clusters development, as well as the demand from elected representatives and States across the length and breadth of the Country, a new 1,000 clusters development program may soon be initiated.

Minister of State, Sadhvi Niranjan Jyoti further added that through the mission people are getting basic facilities and hence several development options are becoming possible. She emphasised that the development of clusters will also have positive repercussions on the challenges our cities face. Shri Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Rural Development informed that, since the launch, Integrated Cluster Action Plans of 288 clusters have been developed and Detailed Project Reports of 240 clusters have been approved by the concerned States, where on-ground work is already underway. A total investment of over Rs. 28,075 crore has been approved in these clusters out of which works worth Rs. 6,689 crore has already been implemented. He also emphasised on convergence of different schemes happening through the Mission.

Panchayat members, SHG women and officials from 13 States shared their cluster development experiences. Kailash Girishwar, CEO, Zila Parishad, Prakasam District explained various employment options created and highlighted that reverse migration is happening. Shri. Mayur Dixit, CDO, Uddham Singh Nagar was accompanied by the panchayat members from Paheniya cluster. He highlighted as to how private sector investment and CSR support has been mobilized by them through organising investment symposium focused on the cluster’s handicraft sector development and is showing positive results. Similarly, representatives from Gujarat, Rajasthan, Telangana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Kerala, Chhattisgarh, Mizoram and Punjab also showed progress being made in provision of basic amenities as well as increased employment opportunities in the clusters.

Shri Prashant Kumar, Special Secretary and other senior officials from Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Micro, Small &
Medium Enterprises and National Capital Region Planning Board attended the event.
Press Information Bureau  
Government of India  
Ministry of Rural Development

4th Anniversary of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) on 21st February, 2020

300 Rural clusters with increasing urbanization envisaged to be developed in a timebound and holistic manner Spurred by the success of Rurban clusters, NITI Aayog proposes a new and extended programme for over a 1,000 clusters in next 3 years

The 4th Anniversary of the launch of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) will be observed tomorrow. On 21st February 2016, the Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Mission with the vision to deliver catalytic interventions to rural areas on the threshold of growth.

Undertaken by the Union Ministry of Rural Development, the SPMRM focuses on cluster-based integrated development through Spatial Planning. Rurban clusters are identified across the country’s rural areas showing increasing signs of urbanization - i.e. increase in population density, high levels of non-farm employment, presence of growing economic activities and other socioeconomic parameters.

The Mission aims to transform these Rurban clusters by stimulating local economic development, enhancing basic services, and creating well planned Rurban clusters. This would lead to holistic development of the region and encourage integrated and inclusive rural development.

Under the mission 300 Rurban clusters are envisaged to be developed in a timebound manner. Of these 296 clusters have been selected and number of Integrated Cluster Action Plans (ICAPs) approved are 288 and Detailed Project Reports of 240 have been approved.

SPMRM is a Core Centrally Sponsored Scheme, The Mission has two fund streams: (1) Convergence through various Central sector schemes, centrally sponsored schemes, State sector/ sponsored schemes/ programmes, CSR funds, and (2) Critical Gap Funds (CGF). It provides for CGF upto Rs. 30 crore per cluster for Non-tribal clusters, and upto Rs. 15 crore per cluster for Tribal and Hilly State clusters.

Currently, total Central Share funds released till date is Rs. 1,842.97 cr. Total investment approved in 288 ICAPs is Rs.28,075 cr with convergence being Rs.21,194 cr and Rs. 6,882cr. Of this, total expenditure, as on 30th November 2019, was Rs.6,689 cr of which Rs. 5,619 cr formed convergence and Rs. 1,071 cr under CGF. The CGF Funds release is expected to cross target of Rs. 1,200 crore by 31st March, 2020.

Infrastructure planned in these clusters includes provision of 24/7 water supply to all households, Solid and Liquid Waste Management facilities at the household and cluster level, provision of Inter and Intra village roads within the cluster, adequate street lights and public transport facilities using green technologies. Economic amenities in a cluster comprise various thematic areas in the sectors of Agri Services and Processing, Tourism, and Skill Development to promote Small and Medium Scale Enterprises.

SPMRM clusters focus selecting interventions from the following components depending on locally felt need as identified during baseline survey:


Going forward, the Ministry of Rural Development is taking steps to expedite Mission’s on-ground progress. The Mission is seeking extension by 2 years to complete all the identified works. Ministry has received requests on several forums and communications from many States and elected officials to allocate more Rurban clusters. NITI Aayog has recently shared with Ministry that based on learning from the success of the Rurban clusters, a new and extended programme for over a 1,000 clusters in next 3 years may be planned.

In words of the Prime Minister, the objective is to develop the clusters with आला गाँव की..., सुविधाएं शहर की...’ by providing all the basic amenities, infrastructure as well as economic development opportunities in an integrated and timebound manner.

****

APS/PK
Release of Success Story

Hon’ble Minister Shri. Narendra Singh Tomar addressing the participants
अनुभाग बः:

SPMRM की 4 वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रेस कवरेज
श्यामा प्रसाद मुखर्जी 'र्बन मिशन' (एसपीएमआरएम) के तहत अब शहरी सुविधाओं के साथ विकास कार्यों की पल-पल की खबर जिओ टेंगिंग की मदद से मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 300 क्लस्टर में समग्र विकास योजना के बाद अब इसे एक हजार नए क्लस्टर में शुरू करने का एलान किया है।

इस योजना में शहरों से सटी ग्रामीण आबादी में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, रोड कनेक्टिविटी, रोजगार जैसी योजनाओं को एक साथ लाकर विकास किया जा रहा है। सोमवार को दिल्ली के अंबेडकर भवन में योजना के चार साल पूरे होने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस योजना की समीक्षा की।

तोमर ने इस अवसर पर जिओ टैंगिंग एप की भी शुरुआत की। उन्होंने एक हजार नए क्लस्टर की विस्तृत योजना का खाका पेश किया। यह योजना 2016 में शुरू हुई थी। चार सालों में 296 क्लस्टरों में काम लगभग पूरा हो गया है। इसमें 1,842.97 करोड़ रुपये खर्च हुए।
रुर्बन मिशन में भारतीय संस्कृति और परंपरा की भावना का समावेश है : तोमर

25/02/2020 - by Media Passion

नई दिल्ली : केन्द्रीय ग्रामीण विकास, घंटावटी राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन के चौथे वार्षिक समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा रुर्बन मिशन में भारतीय संस्कृति और परंपरा की भावना का समावेश है।

इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी, 2016 को विकास की दशहरी पर खड़े ग्रामीण इलाकों के उद्धरक प्रयासों की संकल्पना के साथ की थी। इसका उद्देश्य समावेश और समानबद्धता के लिए सामुदायिक प्राग्य को ध्यान में रखा गया और कल्स्टर पहुंच इस बारे में बहुत लाभदायक है। उन्होंने यह अनुरोध किया कि लोगों की ‘सबका साथ सबका विकास’ के उद्देश्य को हासिल करने के लिए समर्पित होना चाहिए और गांव और ग्रामीण भारत के विकास के लिए सामुदायिक भावना के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा जब सामुदायिक भावना और प्रयासों में बढ़ोतरी होती है तब केंद्र और राज्य कल्स्टरों की विकास के लिए मिलकर काम करने और सभी योजनाओं की इस उद्देश्य के दिशा में समावेशी बनाया जाएगा।

ग्रामीण विकास सचिव श्री राजेश भूषण ने रुर्बन मिशन के अंतर्गत सकारात्मक हस्तक्षेप और सफलता की कार्यनी की प्रशंसा की। उन्होंने अनुभव और कल्स्टरों की साझा करने के लिए विभिन्न राज्यों एवं पंचायती राज संस्थाओं के साथ प्रतिभागियों की समागम किया, ताकि अन्य लोग उन्हें कुछ सिखें और समय कार्यवाहन में सुधार कर सकें। श्री भूषण ने मिशन के तहत उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मंत्रालय द्वारा अब तक 300 कल्स्टर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 296 को मंजूरी मिल गई है।

मिशन के महत्व के बारे में बात करने हुए श्री भूषण ने कहा कि यह मिशन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं का मूल्य है, जिससे योजनाबद्ध और संगठित तरीके से क्षेत्र का समग्र विकास होता है। उन्होंने बताया कि यह मिशन रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ यह ग्रामीण भारत में अपशिष्ट प्रधान, स्टार्ट कल्स्टर, पहुंच द्वारा जलापूर्ति, सड़कें, कृषि प्रसंक्षेपण और प्राथमिक उपायों में मूल्य वृद्धि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है और यह गांवों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
जनजातीय रुबबन क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहा है मंगा
रुबबन मिशन के वार्षिक वर्षगांठ पर प्रखंड प्रशासन ने गिनायी उपलब्धि
रुबर्बन मिशन का कार्यक्रम की चौथी वर्षगांठ मनाई गयी बतवाइँ। श्रमण प्रसाद मुखर्जी रुबर्बन मिशन कार्यक्रम की चौथी वर्षगांठ रुबर्बन उत्सव के रूप में मनाया गया। बीडिओ दिनेश दुर्गाराम ने बताया कि प्रवंड के मंगाज और उवकामांड रुबर्बन कल्स्टर के रूप में भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण संस्कृति बनाये रखना है। इन ग्रामों में एंड्रू और राज्य सरकारों का एक-टू-एक स्तर पर संयुक्त चयनित पंचायतों में समक्ष विकास किया जा रहा है।

उल्लेखित रुबर्बन मिशन का लक्ष्य भारत सरकार के उद्देश्यों के साथ-साथ पंचायतों के लाभ को विकास के रूप में परिवर्तित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य रुबर्बन के रूप में एकता, समृद्धि और स्वाभाविक संस्कृति का विकास है। इसके लिए, सरकार ने विभिन्न प्रोजेक्टों का समावेश किया है, जिनमें समुदाय उड़ान, अर्थव्यवस्था और राजनीति का समावेश है। इन्हें लेकर ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए कार्यकर्ताओं का प्रयास किया जा रहा है।

जिसमें शहीद के नाम पर विशेष उल्लेख मिला रहा है, वह 'रुबर्बन' का योग्य वर्तमान नाम है। इस डिप्लोमा ने विभिन्न संस्थाओं का उत्सव को आशीर्वाद किया है। उन्होंने उद्देश्यों के लिए एक संगठन की रूपरेखा की है जो इस कार्यक्रम को सही राह से निर्देशित करेगा।
पंचायत को बाजार के रूप में करेंगे विकसित: दास

सेवा के प्रदान करते हुए हमने ऐसा किया जो नये क्षेत्र की अवधारणाओं को दिखाया। बाजार में हमने नए उत्पादों को लाया जो लोगों के लिए नये संवेदनशीलताओं को साझा करता है।

बाजार में हमने नए उत्पादों को लाया जो लोगों के लिए नये संवेदनशीलताओं को साझा करता है।

सेवा के प्रदान करते हुए हमने ऐसा किया जो नये क्षेत्र की अवधारणाओं को दिखाया। बाजार में हमने नए उत्पादों को लाया जो लोगों के लिए नये संवेदनशीलताओं को साझा करता है।
रांची। राष्ट्रीय रुब्न मिशन की चौथी वर्षगांठ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नयी दिल्ली में सोमवार को नेताजी सुभाष चरण रांची राज्य में साधौरी निर्जन ज्योति को पीएचएम अवार्ड से अवार्ड मिलने का समापन किया गया। साधौरी निर्जन ज्योति रांची के लोकमान्य राम मिशन में मात्र किसी ने भी निर्जन ज्योति को चुनी थी। इस अवार्ड के साथ साधौरी निर्जन ज्योति ने सीमा भारत के बाहर भारत के लिए भारतीय विदेशों में भारतीय कला का बयान किया।
रब्बन योजना के चौथे सालगिरह समारोह में कवीरधाम हुआ शामिल
नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जिले के दो महिला रब सहयोगी समूह की सदस्यें ने बांटे अपने अनुभव
महिलाओं ने मंत्री को बताए भोर कलेवा स्वप्नपाहर से होने वाले लाभ

कार्यक्रम (नवम्बर 2021)। रक्षात्मक ऑपरेशन पूर्वाञ्चल मिशन के पूर्व अध्यक्ष का आयोजित एक निम्नांकित कार्यक्रम में प्रस्तरित रक्षा मंत्री से कृपया कर केला जिले के दो महिला रब, स्वतंत्रता समूह के सदस्य ने अपने अनुभव केंद्र स्थान पर रखा। यह प्रकरण को स्हर आयोजक अहकार कार्यक्रम, 15 दिसंबर को, दो दिनों में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया।

इसमें जिले के महत्वपूर्ण विशेष विषयों का विवरण, स्वप्नपाहर केंद्र की अनावरण गति पैरामेटर, इस पुस्तक में कहाँ हैं तिनका विचार, जिसका दल नहीं है। किसी विशेष विश्लेषण का अभाव में हुआ के कारण पूरा अवधारणा करने वाला मुख्य प्रोफेसर इंजीनियर के के विज्ञान में नेशनल केंद्र के रक्षा केंद्र में स्वप्नपाहर केंद्र के साथ-साथ मंत्री शहीद तोमर के केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ रहा।

महिलाओं ने बताए अपने अनुभव। शिक्षा कार्यक्रम के में, नेशनल विश्वविद्यालय अवलोकनीय विषय समूह के सरकार के कार्यक्रम विकास उपाध्यक्ष के, ने निकली दोनों गांव शहीद के केंद्र से आयोजित कार्यक्रम में नेशनल केंद्र विकास उपाध्यक्ष के में। नागरिक उपरोक्त रब से संबंधित है। इस प्रकार के नागरिक उपरोक्त रब से संबंधित है। इस प्रकार के नागरिक उपरोक्त रब से संबंधित है।
Section B: Press Coverage on occasion of 4th Anniversary of SPMRM
The fourth Anniversary of the launch of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) was observed today. On 21st February 2016, Prime Minister Narendra Modi had launched the Mission with the vision to deliver catalytic interventions to rural areas on the threshold of growth.

On 21st February 2016, Prime Minister Narendra Modi had launched the Mission with the vision to deliver catalytic interventions to rural areas on the threshold of growth. This will lead to the holistic development of the region and encourage integrated and inclusive rural development.
The fourth Anniversary of the launch of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) was observed today. On 21st February 2016, Prime Minister Narendra Modi had launched the Mission with the vision to deliver catalytic interventions to rural areas on the threshold of growth.

The Mission aims at transforming these Rurban clusters by stimulating local economic development, enhancing basic services and creating well planned Rurban clusters. This will lead to the holistic development of the region and encourage integrated and inclusive rural development.

In an exclusive interview with All India Radio News, Secretary Rural Development Rajesh Bhushan outlined the objectives of the mission.

Spurred by the success of Rurban clusters, NITI Aayog has recently proposed a new and extended programme for over 1,000 clusters in next three years. In Sikkim, three such clusters are being developed in the South, East and West districts.
Rural areas are the cell of the national body and the cell-life must be healthy and developed for the national body to be healthy and developed, they say! While the future of India lies in the villages, PM Modi, back in 2016 had launched a Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission with the vision to deliver catalytic interventions to rural areas on the threshold of growth. Celebrating the 4th anniversary of the launch of the said Mission today, here's a small folio as flashed by the Centre, schooling you about the SPMRM in deets.

Undertaken by the Ministry of Rural Development, the SPMRM has its focus on cluster-based integrated development through spatial planning. Rurban
clusters are identified across the country’s rural areas showing increasing signs of urbanization i.e. increase in population density, high levels of non-farm employment, presence of growing economic activities and other socioeconomic parameters.

While the mission aims to transform these Rurban clusters by stimulating local economic development, enhancing basic services, and creating well planned Rurban clusters, this is capable of leading to holistic development of the region and encourage integrated and inclusive rural development.

Under the mission 300 Rurban clusters are envisaged to be developed in a timebound manner, of these 296 clusters have been selected and number of Integrated Cluster Action Plans approved are 288. SPMRM is a Core Centrally Sponsored Scheme, where the Mission has two fund streams. Currently, total central share funds released till date is Rs. 1,842.97 crores and the total investment approved in 288 ICAPs is Rs. 28,075 crores.

**Infrastructure planned in these clusters include provision of 24/7 water supply to all households, Solid and Liquid Waste Management facilities at the household and cluster level, provision of inter and intra village roads within the cluster, adequate street lights and public transport facilities using green**
technologies. Economic amenities in a cluster comprise various thematic areas in the sectors of Agri Services and Processing, Tourism, and Skill Development to promote Small and Medium Scale Enterprises.

Going forward, the Ministry of Rural Development is taking steps to expedite mission’s on-ground progress. The mission is seeking extension by 2 years to complete all the identified works. Ministry has received requests on several forums and communications from many States and elected officials to allocate more Rurban clusters. NITI Aayog has recently shared with Ministry that based on learning from the success of the Rurban clusters, a new and extended programme for over a 1,000 clusters in next 3 years may be planned. In words of the Prime Minister, the objective is to develop the clusters with आत्मा गॉव की, सुविधाएं शहर की’ by providing all the basic amenities, infrastructure as well as economic development opportunities in an integrated and time bound manner.
Rurban Mission embodies spirit of Indian culture of community living: Narendra Singh Tomar

Press Trust of India | New Delhi Last Updated at February 24, 2020 23:04 IST

The Mission which was launched by Prime Minister Narendra Modi on February 21 2016, with the vision to deliver catalytic Union Minister Narendra Singh Tomar on Monday said the Centre's flagship scheme Rurban Mission, embodies the spirit of Indian culture and tradition which is that of community living.

The objective of the Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) is to develop the cluster of rural villages in a holistic manner by providing all the basic amenities, infrastructure as well as economic development opportunities in an integrated and time bound manner.

Speaking at a ceremony to mark the fourth anniversary of the mission, Tomar, the Union Minister for Rural Development, said the Rurban Mission embodies the spirit of the Indian culture and tradition which is that of community living.

The community perspective has to be kept in mind for holistic development of a region and cluster approach is very fruitful in that regard, Tomar said in an official statement.

He said when the community spirit and effort increases, the Centre and states will work together for development of clusters and all schemes will be made convergent towards that objective.

The Union Minister said that the amount of funding given to this scheme is mostly for gap funding but the central and state government funding together can have a good impact on development of clusters.
The Union Minister for Rural Development, Panchayati Raj, Agriculture and Farmers’ Welfare Narendra Singh Tomar today inaugurated the 4th Anniversary celebration of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission at Dr. Ambedkar International Centre in New Delhi. The Mission was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi on 21st February 2016, with the vision to deliver catalytic interventions to rural areas on the threshold of growth. The objective is to develop the clusters in a holistic manner by providing all the basic amenities, infrastructure as well as economic development opportunities in an integrated and time bound manner. Addressing the gathering after lighting the ceremonial lamp, Union Minister Shri Narendra Singh Tomar congratulated all the participants on the 4th Anniversary of the Mission and said that the Rurban mission embodies the spirit of Indian culture and tradition which is that of community living. Shri Tomar said that the community perspective has to be kept in mind for holistic development of a region and cluster approach is very fruitful in that regard. The Minister urged that people should be dedicated towards achieving the objective of ‘sabka saath sabka vikas’ and work towards development of villages and rural India with a community spirit. He said that when the community spirit and effort increases then Centre and State will work together for development of clusters and all schemes will be made convergent towards that objective. The Union Minister said that the amount of funding given to this scheme is mostly for gap funding but the Central and State government funding together can have a good impact on development of clusters.

Narendra Singh Tomar said that any project in its nascent stage faces a lot of hurdles or difficulties but when all the people decide to work together in unison then development will definitely be achieved. The Minister hailed the efforts of all involved with the SPM Rurban Mission and urged all to work harder for making this mission a success and increase the overall level of development especially in Rural India. Secretary, Department of Rural Development Shri Rajesh Bhushan hailed the positive interventions and success stories under the Rurban Mission and welcomed all the participants from various States and Panchayati Raj institutions to share their experiences and difficulties faced so that others can learn from them and improve overall implementation. Shri Bhushan highlighted the achievements under the mission and said that 300 clusters have been allocated so far by the Ministry out of which 296 have been approved. Talking about the importance of the Mission, the Secretary said that this mission leads to convergence of the schemes of Union Government and the State Governments which leads to overall development of the region in a planned and organized manner. Shri Bhushan said that the critical gap funding aspect of the mission leads to further convergence and improves efficiency in overall implementation by providing financial assistance for various projects. He further informed that the mission provides good employment opportunities, basic as well as urban facilities to rural India such as waste management, smart classrooms, piped water supply, Roads, Agro processing and value addition to primary produce etc and therefore is critical for holistic development.
Rurban Mission embodies spirit of Indian culture of community living Narendra Singh Tomar

PTI February 24, 2020 23:02 IST

New Delhi, Feb 24 (PTI) Union Minister Narendra Singh Tomar on Monday said the Centre's flagship scheme Rurban Mission, embodies the spirit of Indian culture and tradition which is that of community living.

The Mission which was launched by Prime Minister Narendra Modi on February 21 2016, with the vision to deliver catalytic interventions to rural areas on the threshold of growth.

The objective of the Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) is to develop the cluster of rural villages in a holistic manner by providing all the basic amenities, infrastructure as well as economic development opportunities in an integrated and time bound manner.

Speaking at a ceremony to mark the fourth anniversary of the mission, Tomar, the Union Minister for Rural Development, said the Rurban Mission embodies the spirit of the Indian culture and tradition which is that of community living.

The community perspective has to be kept in mind for holistic development of a region and cluster approach is very fruitful in that regard, Tomar said in an official statement.

He said when the community spirit and effort increases, the Centre and states will work together for development of clusters and all schemes will be made convergent towards that objective.

The Union Minister said that the amount of funding given to this scheme is mostly for gap funding but the central and state government funding together can have a good impact on development of clusters. PTI JTR CK
Govt to encourage formation of "cluster villages"

New Delhi, Feb 21 (IANS) The Central government, under the Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission, is encouraging formation of "cluster villages" so as to enable them to get facilities available in urban areas.

The mission, which got off the ground on February 21, 2016, has in its wing 300 such village clusters, according to officials of the Rural Development Ministry.

"The aim is to create at least 1,000 such clusters," said an official on the fourth anniversary of the launch of the mission.

"The objective of the mission is to make available city-like facilities in villages, which should now join the development competition. As most of our population lives in villages, there is need for "smart villages" alongside "smart cities"," said the official.

The government is working on a development model that has villages as its soul with facilities on lines of cities. The government has set aside Rs 21,000 crore for the project, said the official.

He said the facilities proposed to be available in such cluster villages would include 24-hour water supply, trash management, public transport, small and medium industries, citizen service centre, digital literacy, improved healthcare, sports infrastructure and skill development centres.

The official cited many instances of the government initiative. One such example is 19 villages in Andhra Pradesh's Vizianagaram district.

The 19 villages faced severe drinking water shortage. In Konda Lakshmipuram village -- located hardly a km from the block headquarters -- there were only six handpumps. The government facilitated linking of these villages and with an expenditure of Rs 16 crore helped set up a 10,000-litre water tank besides other development projects. "Most villages in the area now have tap water supply," the official said.

--IANS

hindi/prs
NITI Aayog proposes to extend Rurban Mission (SPMRM) to over 1,000 clusters

February 21, 2020  The ID Staff

New Delhi: The 4th anniversary of the launch of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) will be observed today. On 21 February 2016, Prime Minister Narendra Modi launched the Mission with the vision to deliver catalytic interventions to rural areas on the threshold of growth.

Undertaken by the Union Ministry of Rural Development, the SPMRM focuses on cluster-based integrated development through spatial planning. Rurban clusters are identified across the country’s rural areas showing increasing signs of urbanization, increase in population density, high levels of non-farm employment, presence of growing economic activities and other socioeconomic parameters.

The Mission aims to transform these rurban clusters by stimulating local economic development, enhancing basic services, and creating well-planned rurban clusters. This will lead to the holistic development of the region and encourage integrated and inclusive rural development.

Under the mission 300 rurban clusters are envisaged to be developed in a timebound manner. Of these 296 clusters have been selected and 288 Integrated Cluster Action Plans (ICAPs)
have been approved. Detailed Project Reports of 240 clusters have been approved.

SPMRM is a Core Centrally Sponsored Scheme. The Mission has two fund streams – convergence through various Central sector schemes, centrally sponsored schemes, State sector/ sponsored schemes/ programmes, CSR funds; and Critical Gap Funds (CGF). It provides for CGF up to Rs 30 crore per cluster for non-tribal clusters, and up to Rs 15 crore per cluster for tribal and hilly clusters.

Currently, the total Central share funds released is Rs 1,842.97 crore. Total investment approved in 288 ICAPs is Rs 28,075 crore with convergence being Rs 21,194 crore and Rs 6,882 crore. Of this, total expenditure as on 30 November 2019, was Rs 6,689 crore of which Rs 5,619 crore formed convergence and Rs 1,071 crore under CGF. The CGF release is expected to cross the target of Rs 1,200 crore by 31 March 2020.

Infrastructure planned in these clusters includes provisions for 24/7 water supply to all households, solid and liquid waste management facilities at the household and cluster level, provision of inter and intra village roads within the cluster, adequate street lights and public transport facilities using green technologies. Economic amenities in a cluster comprise various thematic areas in the sectors of agriculture services and processing, tourism, and skill development to promote small and medium scale enterprises.

SPMRM focuses on selecting interventions in components depending on locally felt needs in different clusters. The baseline survey identified sanitation, piped water supply, solid and liquid waste management, village street lights and electrification, access to village streets with drains, inter-village roads connectivity, public transport, skill development training linked to economic
activities, agri-services processing and allied activities, health, education, digital literacy, citizens service centres, LPG gas connection, environment, employment generation and self-help groups formation, tourism promotion, sports infrastructure, social infrastructure, rural housing, and social welfare, as the key components.

Going forward, the Ministry of Rural Development is taking steps to expedite the Mission’s on-ground progress. The Mission is seeking an extension by 2 years to complete all the identified works. The Ministry has received requests on several forums and communications from many states and elected officials to allocate more rurban clusters. NITI Aayog has recently shared with the Ministry that based on learning from the success of the rurban clusters, a new and extended programme for over 1,000 clusters in next 3 years may be planned.

In words of the Prime Minister, the objective is to develop the clusters with ‘Aatma Gaon Ki, Suvidhaen Shehar Ki’ by providing all the basic amenities, infrastructure as well as economic development opportunities in an integrated and timebound manner.
February 20, 2020, New Delhi: The 4th Anniversary of the launch of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) will be observed tomorrow. On 21st February 2016, the Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Mission with the vision to deliver catalytic interventions to rural areas on the threshold of growth.

Undertaken by the Union Ministry of Rural Development, the SPMRM focuses on cluster-based integrated development through Spatial Planning. Rurban clusters are identified across the country’s rural areas showing increasing signs of urbanization – i.e. increase in population density, high levels of non-farm employment, presence of growing economic activities and other socioeconomic parameters.

The Mission aims to transform these Rurban clusters by stimulating local economic development, enhancing basic services, and creating well planned Rurban clusters. This would lead to holistic development of the region and encourage integrated and inclusive rural development.

Under the mission 300 Rurban clusters are envisaged to be developed in a timebound manner. Of these 296 clusters have been selected and number of Integrated Cluster Action Plans (ICAPs) approved are 288 and Detailed Project Reports of 240 have been approved.

SPMRM is a Core Centrally Sponsored Scheme; The Mission has two fund streams: (1) Convergence through various Central sector schemes, centrally sponsored schemes, State sector/ sponsored schemes/ programmes, CSR funds, and (2) Critical Gap Funds (CGF). It provides for CGF upto Rs. 30 crore per cluster for Non-tribal clusters, and upto Rs. 15 crore per cluster for Tribal and Hilly State clusters.

Currently, total Central Share funds released till date is Rs. 1,842.97 cr. Total investment approved in 288 ICAPs is Rs.28,075 cr with convergence being
Rs.21,194 cr and Rs. 6,882cr. Of this, total expenditure, as on 30th November 2019, was Rs.6, 689 cr of which Rs. 5,619 cr formed convergence and Rs. 1,071 cr under CGF. The CGF Funds release is expected to cross target of Rs. 1,200 crore by 31st March, 2020.

Infrastructure planned in these clusters includes provision of 24/7 water supply to all households, Solid and Liquid Waste Management facilities at the household and cluster level, provision of Inter and Intra village roads within the cluster, adequate street lights and public transport facilities using green technologies. Economic amenities in a cluster comprise various thematic areas in the sectors of Agri Services and Processing, Tourism, and Skill Development to promote Small and Medium Scale Enterprises.

SPMRM clusters focus selecting interventions from the following components depending on locally felt need as identified during baseline survey:


Going forward, the Ministry of Rural Development is taking steps to expedite Mission’s on-ground progress. The Mission is seeking extension by 2 years to complete all the identified works. Ministry has received requests on several forums and communications from many States and elected officials to allocate more Rurban clusters. NITI Aayog has recently shared with Ministry that based on learning from the success of the Rurban clusters; a new and extended programme for over a 1,000 clusters in next 3 years may be planned.

In words of the Prime Minister, the objective is to develop the clusters with आत्मा गाँव की….. सुविधाएं शहर की‘ by providing all the basic amenities, infrastructure as well as economic development opportunities in an integrated and time bound manner.
National Web News

https://smestreet.in/sectors/unio
rural-development-minister-
narendra-singh-tomar-initiates-
the-4th-anniversary-celebration-
of-shyama-prasad-mukherjee-
rurban-mission/

Union Rural Development
Minister Narendra Singh
Tomar Initiates The 4th
Anniversary Celebration Of
Shyama Prasad Mukherjee
Rurban Mission

Tending to the social event subsequent to lighting the
formal light, Union Minister Narendra Singh Tomar
praised all the members on the fourth Anniversary of the
Mission and said that the Rurban strategic: the soul of
Indian culture and convention which is that of network
living.

The Union Minister for Rural Development, Panchayati Raj,
Agriculture and Farmers’ Welfare Narendra Singh Tomar today
introduced the fourth Anniversary festival of Shyama Prasad
Mukherjee Rurban Mission at Dr. Ambedkar International
Centre in New Delhi. The Mission was propelled by Prime
Minister Shri Narendra Modi on 21st February 2016, with the
to convey synergistic interventions to key areas on the edge of
development. The goal is to build up the bunches in a
comprehensive way by giving all the fundamental
enhancements, foundation just as financial improvement
openings in a coordinated and time bound way.

Tending to the social event subsequent to lighting the formal
light, Union Minister Narendra Singh Tomar praised all the
members on the fourth Anniversary of the Mission and said that
the Rurban strategic: the soul of Indian culture and convention
which is that of network living. Tomar said that the network
viewpoint must be remembered for comprehensive
advancement of an area and launch a productive in
such manner. The Minister asked that individuals ought to be
centered towards accomplishing the goal of ‘satya saath sabka
vikaas’ and work towards improvement of towns and country
India with a network soul. He said that when the network soul
and execution expands then Center and State will cooperate for
improvement of groups and all plans will be made united
throughout that objective.

The Union Minister said that the measure of substituting given
to this plan is generally for hole financing however the Central
d and State government substituting together can goodness affect
improvement of groups. Shri Tomar said that any task in its
beginning stage faces a great deal of obstacles or challenges
however when all the individuals choose to cooperate as one
their improvement will be accomplished. The Minister hailed the
efforts of all associated with the SPM Rurban Mission and
asked all to work more diligently for making this crucial
achievement and increment the general degree of improvement
particularly in Rural India.

Secretary, Department of Rural Development Shri Rajesh
Bhushan hailed the positive mediations and examples of
overcoming adversity under the Rurban Mission and received
all the members from different States and Panchayati Raj
foundations to share their encounters and troubles confronted
with the goal that other can gain from these and improve by and
large usage. Shri Bhushan featured the accomplishments under
the mission and said that 300 groups have been designated so
far by the Ministry out of which 206 have been affirmed.

Discussing the significance of the Mission, the Secretary said
that this crucial to union of the plans of Union Government and
the State Governments which promote generally improvement of
area in an arranged and sorted out way. Shri Bhushan said
that the basic hole substituting part of the mission promulgates
further combination and improves productivity in by and large
usage by giving budgetary help to different tasks. He further
said that the crucial great work openings, essential just as
urban offices to rural India, for example, elevated the
executive, town study tools, furnished water supply, Roads,
Agri preparing and network expansion to essential produce and
so forth and along these lines is basic for all encompassing
improvement.
Feb 24, 2020

Govt plans to construct 1,000 more urbanized clusters in rural areas, says Rural Development Minister Narendra Singh Tomar

Union Minister for Rural Development Narendra Singh Tomar has said, after evaluating the success rate of Rurban Clusters scheme, government is intending to move ahead to construct 1,000 more urbanized clusters in rural areas

Speaking at the of 4th Anniversary Celebration function of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission, SPMRM in New Delhi today, Mr Tomar said, sense of mutual cooperation between people, who want urbanization in their rural space and concerned ministry officials will be instrumental in ensuring the success of the scheme.

On the occasion, the Minister launched GeoRurban, a mobile app to be used for Geo-tagging for the assets in the rurban clusters.

AIR correspondent reports that this flagship scheme of Centre, launched by Prime Minister Narendra Modi on 21st February in 2016, aims at transforming these Rurban clusters by stimulating local economic development, enhancing basic services, and creating well planned Rurban clusters.
MIZORAM & REGION

4th Anniversary of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (SPMRM) was held

Mizawl, Feb 24

A one-day Commemoration on 4th Anniversary of Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (SPMRM) was held today, the 24th February, 2020 at the State Institute of Rural Development Conference Hall. The programme was organized by the Field Outreach Bureau, Aizawl, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India and sponsored by the Rural Development Department, Government of Mizoram.

Smt. Lalzaptui, Block Development Officer, Thingpuihinkh, delivered a lecture on SPMRM as Resource person and Dr. A. Romboucha Sharma, Field Projects Officer, FOB Aizawl gave a short speech highlighting the Rurban Mission and on Ek Bharat Shreshtha Bharat (EBSB) during the event.

Smt. Lalzaptui said that Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (SPMRM) is a scheme launched by Government of India in 2016 to deliver integrated project based infrastructure to the rural areas, which will also include development of economic activities and skill development. The preferred mode of delivery is through Public Private Partnership while using various funding schemes for financing the Mission.

The main objective of the Programme is to disseminate information and education to the people on the above Mission of the Government of India and implemented by the Rural Development Department, Government of Mizoram.

Smt. Lalzaptui added that the Mission has progressed since its launch in 2016. Out of the mandated 500 clusters, 295 clusters have been identified and approved across 29 States and 8 Union Territories. The State Governments identifies the clusters in accordance with the Framework for Implementation prepared by the Ministry of Rural Development.

For the selection of clusters, the Ministry of Rural Development is adopting a scientific process of cluster selection which involves an objective analysis at the District, Sub District and Village level, of the demography, economics, tourism and pilgrimage significance and transportation corridor impact. While the Ministry, following this analysis, would provide a suggestive list of sub-districts to the State, the State Governments would then select the clusters following a set of indicated principles included in the Framework for Implementation.

Speaking about Ek Bharat Shreshtha Bharat, Dr. Romboucha Sharma said that the main objective of Ek Bharat Shreshtha Bharat is to celebrate the Unity in Diversity of our nation and to maintain and strengthen the fabric of traditionally existing emotional bonds among the people of our country, promote the spirit of national integration through a deep and structured engagement among the states and union territories through a year-long planned engagement among states, to showcase the rich heritage and culture, customs and traditions of the states and union territories in the country for enabling people to understand and appreciate the diversity in the country, thus fostering a sense of common identity to create an environment which will promote learning between states by sharing best practices and experiences with an endeavor to attain the new heights of India as a world leader.

Approximately 100 representatives, including officials of the Field Outreach Bureau, Block Development Officer and other line Departments such as ICDS, Power & Electric Dept., Horticulture, Primary Health Centre, Presbyterian English School and local NGO(s) of Thingpuihinkh attended the programme. Cultural programme, Quiz competition and Prize distribution to the winners of the quiz competition were the other main highlights of today's programme.
Gajwel Urban Park in the making with world-class facilities

STATE BUREAU
Gajwel

Gajwel Urban Park, which is being developed at a cost of Rs. 55 crore in 293 acres of forest land adjacent to Gajwel-Wargal road, has been drawing huge crowds during weekends and holidays right before its formal inauguration.

Since it is going to be one of the rarest and largest parks in the State, having over 100 tree species, the park has been attracting VIPs, nature lovers and environmentalists.

On January 1, RM Dobriyal (Additional Principal Conservator of Forests-Social Forest), took his friends and relatives to Gajwel park tour from all the way from Hyderabad. Each and every one of them was impressed by seeing such a wonderful park. It is not only senior IPS officer, Dobriyal, but many officials and public representatives from across Telangana State and other parts of the country were also making a visit to have a glimpse of the lung space and to replicate the same in their respective areas. Since it is having some 38 water bodies, including 5 big lakes, the DFO observed that it was going to be a home for many birds and herbivores such as wild hare in the days to come because the entire park was having fencing now.

The beauty of the 293-acre park is that the forest department to keep most parts of the area intact like the forest. They will further take up the plantation in the area. They are making some development works in a few acres at the entrance of the park and at camping location including a couple of lakes while keeping the rest of it like a natural forest area.

Divisonal Forest Officer, Siddipet, Chepurid Srichar Rao said that the park had something for all the age group people including the women. While there was an open gym for youth, children playing space, Labyrinth plantation and tent facilities, it is yet to be completed, watchtowers and many others for people of all the ages to explore. To have an overview of the 293-acre park, a couple of watchtowers were also being built at various locations. Saying that the works at the Park is almost nearing completion, DFO, Srichar said that Chief Minister K Chandrasekhar Rao, who is representing from Gajwel Assembly Constituency, wanted to have a world-class urban park close to Gajwel town, which is witnessing a rapid development of late. “We have been just working on materialisation of dream under the guidance of a team of experts in the field, he said.

The 14 tent camping facility, which is being built by utilizing the funds under RUBAN scheme, will further provide an opportunity to experience life in forest during the night too. The park is not only going to attract the visitors from Gajwel and its vicinity, it is being developed with an eye to attract to nature lovers from Hyderabad and other parts of the Telangana.

Once the tent camping facility is completed, the DFO said that they would make available the booking facility online to enable the people to book the facility at finger tips. The park will also have two hotels which will exclusively serve some good Telangana recipes to make the visit more memorable.

The DFO further said that they need to construct toilets and besides connecting the park with drinking water facility with an additional budget of Rs. 50 lakh. Once these two works are completed, the park will be thrown open to the public officially.

It has been attracting about 700 visitors during weekends since it had got some mouth-to-mouth publicity locally.
Union Minister for Rural Development Narendra Singh Tomar has said government is intending to move ahead to construct 1,000 more urbanized clusters in rural areas after the success of urban Clusters scheme.

Speaking at the of 4th Anniversary Celebration function of Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission, SPMRM here today, Mr Tomar said, sense of mutual cooperation between people, who want urbanization in their rural space and concerned ministry officials will be instrumental in ensuring the success of the scheme.

On the occasion, the Minister launched GeoRurban, a mobile app to be used for Geo-tagging for the assets in the rurban clusters.

The flagship scheme of Centre, launched by Prime Minister Narendra Modi on 21st February in 2016, aims at transforming these Rurban clusters by stimulating local economic development, enhancing basic services, and creating well planned Rurban clusters.
ગુજરાત:

શયમા પ્રસાદ સુમભારી ઉલ્લેખયોજના દેખણ
મહુવાના ક્લાસટર દેખણ સાત ગામમાં
40 જેટલા પ્રોજેક્ટ કામો કાથ પરાશો

શયમા પ્રસાદ સુમભારી ઉલ્લેખયોજના દેખણ મહુવાના તાલુકાના
માટે પૂર્વ તમામ ગામના કસ્તર થી થી થી પણ તથા
ત્રણ વખતના પ્રવાસના દરમિયાન 21 એપ્રિલ, 2020 જનરલ સુમભારી ઉદ્યોગવાળો માટે હુદ્ધરમ કરવાની માહિતી મળી હતી. આપણે કેમ, કેમ કે હવે મહુવાના તાલુકાના માટે પૂર્વ તમામ ગામના કસ્તર થી થી થી પણ ત્રણ વખતના પ્રવાસના દરમિયાન 21 એપ્રિલ, 2020 જનરલ સુમભારી ઉદ્યોગવાળો માટે હુદ્ધરમ કરવાની માહિતી મળી હતી. 

સાત ગામમાં કેમ 40 જેટલા પ્રોજેક્ટ કામો કાથ પરાશો વિકાસપ્રવાસ પરાશોની.

માણસકીય, આર્થિક તેમજ સામાજિક સાવચેતા પૂરી પાડવા પ્રભાવના પસંદગી 

શ્રેમ નં. સુયાસૃરી - 2

સુયાસૃરી, 2013 ના પ્રભાવ XXI માટે માટે કે પ્રતિ, શ્રેમ નં. 
1. સુયાસૃરી- મોટી પૂર્ણાત્મક પ્રમાણપત્ર, શ્રેમ નં. 2013, 9/12 ે મુલામ પૂર્ણાત્મક પ્રમાણપત્ર (સુયાસૃરી, 2013, 9/12 મુલામ) 2013, 9/12 
2. મેગા પ્રજાતાત્મક પ્રજાતાત્મક, સંબંધિત પ્રેતના પ્રભાવિત પ્રભાવિત પ્રકારે, નં. 2013, 9/12  
3. સુયાસૃરી - પૂર્વ પૂર્વ ની પૂર્વાધારણ
4. સુયાસૃરી, 2013, 9/12 

સુયાસૃરી - 2
Andhra Pradesh
Andhra Pradesh
Section C: Social Media
Section C: Social Media
आत्मा गाँव की, सुविधा शहर की...
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबर्न मिशन के चार वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया...

#SPMRM #RurbanMission #TransformingIndia
Hon'ble Union Minister of Rural Development, Agriculture and Farmers Welfare & Panchayati Raj launched #NICMeitY developed 'GeoRurban' Mobile App for monitoring physical progress of the works under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission.
Narendra Singh To... 

अगर इंसान संकल्प कर ले तो धन के अभाव में भी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है...

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवर्न मिशन के 21 फरवरी को चार वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में शामिल हुआ...

#SPMRM

Narendra Modi and 4 others